MADHYA PRADESH

Summary

- **Antyodaya Anna Yojana**
  Extended the benefits of AAY (Food Grains) under Targeted Public Distribution System to People Living with HIV in subsidized price.

- **Women Policy**
  Inclusion of HIV/AIDs issue in the Women Policy issued by Govt. of Madhya Pradesh. Provision of benefits of various schemes for women infected and affected by AIDS.

- **Legal Aid**
  Legal aid to People Living with HIV

- **Free Treatment**
  Free laboratory/ diagnostic radiological investigation required for diagnosis and management of several clinical conditions of PLHIV.

- **Mobility Support to Pregnant women living with HIV**
  Mobility support to pregnant women living with HIV

- **Nutritional Support to Children living with HIV**
  Nutritional support to Children Living with HIV

- **Prioritizing PLHIV in MNREGA**
  Prioritizing people living with HIV in MNGRGA

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 230] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 5 जून 2014—ज्येष्ठ 15, शक 1936

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जून 2014

क्र. एफ-7-32-2013-उन्तीस-1.—इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 20 मई 2014 के संलग्न परिशिष्ट "अ" निरस्त किया जाता है. इस आदेश में संलग्न परिशिष्ट "अ" की सूची की श्रेणियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का संख्यांक 20) की धारा 10 के प्रावधान अनुसार नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से राज्य में प्राथमिकता परिवार में सम्मिलित किया गया है.

2. राज्य सरकार द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में साईकिल रिक्शा चालक एवं हाथ ठेला चालक श्रेणी के परिवार, ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कामकाजी महिलाएं, ग्रामीण फेरीवाले (स्ट्रीट वेंडर) एवं ग्रामीण क्षेत्र के केशशिल्पी को प्राथमिकता परिवार में सम्मिलित करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं राज्य की मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का लाभ इस आदेश के जारी होने के दिनांक से दिया जाए.

3. इन प्राथमिकता परिवारों में हितग्राही चयन की प्रक्रिया वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

परिशिष्ट "अ"

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत निम्नांकित श्रेणी के परिवारों को उनकी श्रेणी के सम्मुख अंकित तिथि से प्राथमिकता श्रेणी में सम्मिलित किया गया है:—

क्र (1)	श्रेणी (2)	दिनांक (3)
1.	समस्त बीपीएल परिवार.	
2.	समस्त ऐसे व्यक्ति जो मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक हैं एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य.	
3.	ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अन्तर्गत भूमिहीन खेतिहर मजदूर के रूप में पंजीकृत हैं, एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य.	29-7-2013
4.	शहरी क्षेत्रों में साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना एवं हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति, एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य.	
5.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही, एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य.	
6.	अनाथ आश्रम, निराश्रित/विकलांक छात्रावासों में निवासरत बच्चे तथा नि:शुल्क संचालित वृद्धाश्रमों में निवासरत वृद्धजन.	
7.	शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएं.	
8.	शहरी फेरीवाले (स्ट्रीट वेंडर).	23-8-2013
9.	वनाधिकार पट्टेधारी.	
10.	रेलवे में पंजीकृत कुली.	
11.	मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी.	
12.	बन्द पड़ी मिलों में पूर्व नियोजित श्रमिक.	
13.	बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1972 अन्तर्गत परिचय पत्र धारी बीड़ी श्रमिक.	
14.	समस्त भूमिहीन कोटवार.	
15.	कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अन्तर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी.	24-9-2013
16.	नगरीय निकायों में पंजीकृत केशशिल्पी.	
17.	पंजीकृत बहुविकलांक एवं मन्दबुद्धि व्यक्ति.	
18.	एचआईव्ही (एड्स) संक्रमित व्यक्ति. (जो स्वेच्छा से इस योजना का लाभ लेना चाहते हों.)	
19.	मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जाति के परिवार.	
20.	मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जनजाति के परिवार.	3-10-2013
21.	प्रदेश में मत्स्य पालन करने वाले (मछुआ) सहकारी समितियों के अन्तर्गत पंजीकृत परिवार/सदस्य.	1-2-2014
22.	प्राकृतिक आपदा से वर्ष 2013-14 में प्रभावित ऐसे परिवार, जिनकी फसलों के प्राकृतिक आपदा से क्षति 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो.	28-2-2014
23.	प्रदेश के पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालक/परिचालक.	20-5-2014

नोट-1. क्रमांक 6 की श्रेणी के प्रत्येक पात्र हितग्राहियों के लिए पृथक् राशनकार्ड बनाया जाएगा, जिस पर पता संबंधित संस्था का अंकित होगा. संस्था के नाम से कोई संयुक्त राशनकार्ड जारी नहीं किया जाएगा.

नोट-2. क्रमांक 14 की श्रेणी में ऐसे सभी कोटवार जो भूमि स्वामी के रूप में धारण किए जाने वाली भूमि की गणना कर भूमिहीन की श्रेणी में आएंगे, वे शामिल किये जायेंगे. इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि कोटवारों की भूमि की गणना करते समय उनको प्रदान की गई सेवा भूमि को शामिल न किया जाए.

नोट-3. क्रमांक 17 एवं 18 की श्रेणी से संबंधित बहुविकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति तथा एचआईवी (एड्स) संक्रमित व्यक्ति समान्यत: स्वयं परिवार के आश्रित सदस्य होते हैं, इसलिये इस श्रेणी के पंजीकृत व्यक्तियों के प्राथमिक नातेदार अर्थात् माता-पिता, पति-पत्नी, बेटा-बीटी एवं अविवाहित सगे भाई-बहन भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अन्तर्गत खाद्यान्न आवंटन हेतु पात्र माने जाएंगे.

नोट-4. क्रमांक 19 एवं 20 की श्रेणी में ऐसे परिवार को छोड़कर जिनके मुखिया या सदस्य आयकरदाता हो या भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी कार्यालय, शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक अथवा स्वायत्त उपक्रम, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक एवं सहकारी संस्था शामिल हैं, में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी/कर्मचारी हो.

बी. के. चंदेल, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

168

R.No. 792/1
30/6/1

मध्यप्रदेश शासन
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय

एफ 3-1/2008/शासन (2) भोपाल, दिनांक 22/6/2011

JD(Tr)
Consultant
(CSM)

प्रति

[illegible]
[illegible] विकास समिति
[illegible]

विषय:-मध्यप्रदेश की महिला नीति वर्ष 2008-12 के संबंध में।
संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक एड्स/सी.एस.एम./2011/1281 दिनांक 9.3.11.

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। विभाग द्वारा एड्स पीड़ित महिलाओं के लिये पृथक से कोई योजना संचालित नहीं है। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में एड्स पीड़ित महिलाएं भी लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

[illegible]
अवर सचिव
[illegible]
कुटीर एवं ग्रामोद्योग, [illegible]

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश
महिला नीति कक्ष

क्र0 / संसद / मनी / 2011 /

भोपाल, दिनांक 20 / 5 / 11

प्रति,

अवर सचिव,
मंत्रालय,
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग,
भोपाल

विषय:- प्रदेश की महिला नीति 2008-12 का क्रियान्वयन।

संदर्भ: आपका ज्ञापन क्र0 एफ6-4 / वी-11 भोपाल, दिनांक 29.4.11

उपरोक्त विषयांकित संदर्भ में लेख है विभाग की समस्त स्वरोजगार योजनाओं में महिला वर्ग हेतु 30 प्रतिशत लक्ष्य एवं बजट आरक्षित है। एच.आई. वी./एड्स पीड़ित महिलाएं भी उक्त आरक्षित प्रावधान में शामिल है।

प्रतिलिपि:
क्र0 / संसद / मनी / 2011 / 12.11

MAHILA NITI CORRES

170

मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश की

महिला नीति

2008-12

महिला एवं बाल विकास विभाग
मध्य प्रदेश

4. महिलाओं के लिये गुणात्मक स्वास्थ्य सेवायें

नीतिगत प्रावधान

महिलाओं के लिये गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवायें एवं [illegible] की उपलब्धता।

संस्थागत व्यवस्थायें

- प्रत्येक आयु की महिला की स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों एवं सेवाओं की उपलब्धता हेतु संस्थागत व्यवस्थायें।
- महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता हेतु संस्थागत व्यवस्था।
- मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला के लिये संस्थागत सुविधायें उपलब्ध कराना।
- मातृ मृत्युदर, एड्स एवं एनिमिया पर नियंत्रण के लिये समन्वय सुनिश्चित करने के तंत्र को विकसित करना एवं क्रियान्वित करने के लिये निरंतर मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन।
- चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमों में महिला स्वास्थ्य संकेतकों, महिला भ्रूण हत्या संबंधी जानकारी को शामिल करना।

कार्ययोजना

क्र.	गतिविधियाँ	समयावधि	विभाग
4.1	प्रत्येक आयुवर्ग की महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल तथा चिकित्सा संस्थाओं में पृथक से वार्ड एवं सुविधायें एवं सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराना।	2008–12 सतत्	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग
4.2	सभी चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों एवं संबंधित इकाईयों के लिये जेण्डर संवेदनशीलता प्रशिक्षण जिसमें महत्वपूर्ण महिला स्वास्थ्य संकेतकों का समावेश हो। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कैलेण्डर प्रसारित करना।	2008 सतत प्रशिक्षण महिला संकेतकों के अनुसार जिलों का चिन्हांकन एवं कार्ययोजना	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग
4.3	महिलाओं से संबंधित चिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सकों व चिकित्सालय कर्मियों को नवीनतम तकनीकी पद्धति व चिकित्सालय प्रबंधन पर रिफ्रेशर कोर्स	2008–10 एक वर्ष सतत प्रशिक्षण	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4.4	प्रजनन स्वास्थ्य के लिये चिकित्सालयों में आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था स्टाफ, उपकरण, मूलभूत सुविधा एवं मार्ग में प्रसव कक्ष की व्यवस्था, पर्याप्त स्वच्छता और कार्यकताओं की सुविधा	2008–12	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4.5	प्रत्येक ब्लाक स्तर पर चिकित्सालय में महिला गायनाकॉलाजिस्ट की पद	2008–10 एक वर्ष में लक्ष्य प्राप्ति	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

	स्थापना, ग्रामीण स्तर पर पैथोलॉजी लैब की सुविधा उपलब्ध कराई जाये या ए.एन.एम. को पैथोलाजी का प्रशिक्षण दिया जाये जिससे ग्रामीण महिलाओं को सुविधा हो।		
4.6	ब्लाक स्तर पर टेली मेडिसिन केन्द्रों की स्थापना।	2008–10	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4.7	असाध्य रोगों से प्रभावित महिलाओं के स्वास्थ्य की विशेष देखभाल एवं इस संबंध में जानकारी की उपलब्धता।	2008–12	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग
4.8	अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठनों, इकाईयों के सहयोग से महिलाओं के स्वास्थ्य पर कार्ययोजनाओं का क्रियान्वयन व पारदर्शिता	2008–12 निरंतर	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4.9	संस्थागत प्रसव एवं सुरक्षित मातृत्व के लिये कार्ययोजना एवं संसाधनों को बढ़ावा। जिला ब्लाक एवं ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य परामर्श केन्द्रों की स्थापना।	2008–10 प्रथम कार्ययोजना	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग भारतीय चिकित्सा पद्धति
4.10	परिवार कल्याण एवं महिला स्वास्थ्य, एड्स एवं सेक्सुअली ट्रान्समिटेट रोगों एवं उनसे संबंधित कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार एवं लाभ राशि सीधे महिला को प्रदान करना एवं प्रचार प्रसार में पुरूषों की भागीदारी सुनिश्चित करना एवं एड्स पीड़ित महिलाओं के लिये विशेष योजनायें एवं पुनर्वास की व्यवस्था। कार्यक्रमों का वार्षिक मूल्यांकन।	2008–12 सतत्	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जनसंपर्क विभाग
4.11	महिलाओं में एनिमिया पर नियंत्रण के लिये कड़ाई से मॉनिटरिंग एवं कार्ययोजना, प्रचार प्रसार, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना इस हेतु पंचायत संस्थानों, महिला संगठन, स्वसहायता समूहों से सहयोग	2008–12 सतत्	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। महिला एवं बाल विकास विभाग
4.12	आदिवासी एवं ग्रामीण महिला के पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान के उपयोग को बढ़ावा।	2008–12 सतत्	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग भारतीय चिकित्सा पद्धति आदिवासी विकास विभाग
4.13	गरीब महिलाओं को प्रसव के समय निःशुल्क दवायें एवं पौष्टिक आहार की	2008–12 सतत्	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

(574, साउथ सिविल लाईन्स)

क्र. पत्र/32/एचआईव्ही./एड्स/सविसेप्रा/ /2011 जबलपुर, दिनांक / /2011

प्रति,

माननीय न्यायाधीश एवं अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला [illegible] (म०प्र०)

विषय:- एचआईव्ही/ एड्स पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ:- मध्य प्रदेश एड्स नियंत्रण सोसायटी भोपाल का पत्र क्रमांक एड्स/सी. एस. एस/2011/2509/ दिनांक 24.6.2011

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि मध्य प्रदेश के समस्त जिलों द्वारा सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से एचआईव्ही / एड्स पीड़ित व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है। यथानिर्देश कृपया अध्यक्ष, जिला एवं तहसील अधिवक्ता संघ को अधिवक्ताओं के माध्यम से एचआई व्ही. / एड्स पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु अनुरोध करते हुये सहमति प्राप्त करने का प्रयास करें।

([illegible])
सह सचिव

पृष्ठा.क 32/एचआईव्ही./एड्स/सविसेप्रा/ /2011 जबलपुर दिनांक /7/2011

प्रतिलिपि:-

सलाहकार (सिविल सोसायटी) फेसट्रांसेस मध्य प्रदेश एड्स नियंत्रण सोसायटी (सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - म०प्र० शासन) द्वितीय तल, तिलक्का सेंट भवन, [illegible] को उनके पत्र दिनांक 24/6/2011 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।

([illegible])
सह सचिव

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
सतपुड़ा भवन
मध्यप्रदेश

पत्र क्र. CST-18/ART/SC/HA/C-6/2011/929 भोपाल, दिनांक 25/7/2011

प्रति
1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
2. समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक
मध्यप्रदेश

विषय : एचआयव्ही प्रभावित व्यक्तियों की निःशुल्क जांच करने बाबत्।

प्रदेश में एचआयव्ही संक्रमित व्यक्तियों को मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के द्वारा निःशुल्क एन्टी रीट्रोवायरल ट्रीटमेंट (ए.आर.टी.) उपलब्ध कराया जा रहा है। यह उपचार राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के दिशानिर्देशों के अनुसार दिया जा रहा है।

एचआयव्ही प्रभावित व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अन्त्योदय अन्न योजना का लाभ भी एचआयव्ही प्रभावित व्यक्तियों को उनकी पात्रतानुसार प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके है।

नाको द्वारा निर्धारित एआरटी उपचार आरंभ करने के पूर्व एचआयव्ही प्रभावित व्यक्तियों के कुछ बेस लाईन परीक्षण किए जाना आवश्यक होते हैं परन्तु कई बार इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ये परीक्षण नहीं करवा पाते जिससे इनका उपचार प्रभावित होता है।

अतः प्रदेश के समस्त एचआयव्ही प्रभावित व्यक्ति जिनके पास एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्र (आईसीटीसी) द्वारा जारी जांच प्रतिवेदन हो और जिसमें जांच परिणाम एचआयव्ही प्रभावित दर्ज हो, को निम्नानुसार जांचें प्रदेश के समस्त शासकीय चिकित्सालयों द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी जावे :

1. CBC, 2. BL Urea, 3. S Creat, 4. S Bilirubin, 5. SGPT, 6. SGOT (LFT), 7. RBS, 8. Lipid Profile, 9. VDRL, 10. HbsAg, 11. X-ray Chest, 12. Sonography

कृपया उपरोक्त अनुसार एचआयव्ही प्रभावित व्यक्तियों की निःशुल्क जांच के लिए सभी संबंधितों को सूचित करें।

23/7/11
(जे.एन. कंसोटिया)
आयुक्त, स्वास्थ्य

पृ. पत्र क्र. CST-18/ART/SC/HA/C-6/2011/
भोपाल, दिनांक / /2011
प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –
1. परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र.
3. समस्त नोडल अधिकारी, एआरटी केन्द्र, म.प्र.
4. समस्त नोडल अधिकारी जिला एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, म.प्र.

आयुक्त, स्वास्थ्य

175

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
राज्य स्वास्थ्य समिति
बैंक ऑफ इण्डिया भवन, तृतीय तल, अरेरा–हिल्स, जेल रोड
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एन.एच.एम. / एम.एच. / 2014 / 821 भोपाल, दिनांक 02 / 12 / 2014

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
2. समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक,
3. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश

विषयः–एच.आई.व्ही. संक्रमित गर्भवती महिलाओं को मोबिलिटी सपोर्ट उपलब्ध कराने बाबत्।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की गाइडलाईन के अनुसार एच.आई.व्ही. से संक्रमित सभी गर्भवती महिलाओं को ए.आर.टी. की दवायें प्रदान की जाना है। ए.आर.टी. की दवा नज़दीक के किसी भी ए.आर.टी. केन्द्र से दी जा सकती है। अतः इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करें :–

1. समस्त गर्भवती महिलाओं को एच.आई.व्ही. की जांच ऑफर की जावे।
2. एच.आई.व्ही. की जांच गर्भ के पता चलने के उपरान्त यथाशीघ्र एफ.आई.सी.टी.सी. या आई.सी.टी.सी. पर कराई जावे।
3. आई.सी.टी.सी. द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जो गर्भवती महिलाएं एच.आई.व्ही. से संक्रमित पायीं जाती हैं, उन्हें तत्काल नज़दीक के ए.आर.टी. केन्द्र पर पंजीयन हेतु भेजा जावे।
4. एच.आई.व्ही. से संक्रमित गर्भवती महिलाओं को ए.आर.टी. केन्द्र तक आने–जाने हेतु रुपये 300/– का भुगतान किया जावे। गर्भवती महिला को प्रत्येक माह ए.आर.टी. केन्द्र दवा लेने हेतु जाना होगा, अतः राशि रुपये 300/– प्रत्येक माह की एक विज़िट हेतु, सम्पूर्ण गर्भावस्था काल व शिशु के जन्म के उपरान्त के दो माहों तक गर्भवती महिला द्वारा की गयी ए.आर.टी. केन्द्र की विज़िट हेतु किया जावे।
5. ए.आर.टी. केन्द्र द्वारा प्रत्येक एच.आई.व्ही. संक्रमित व्यक्ति को ग्रीन बुक (हरे रंग की डायरी) जारी की जाती है, जिस पर उनकी प्रत्येक विज़िट का विवरण दर्ज होता है। इस किताब को गर्भवती महिला की ए.आर.टी. केन्द्र की विज़िट के सत्यापन के लिए प्रयुक्त किया जावे।
6. मोबिलिटी सपोर्ट हेतु मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत मद क्रमांक–A.1.5.14 में राशि का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्तानुसार समस्त एच.आई.व्ही. संक्रमित गर्भवती महिलाओं को ए.आर.टी. केन्द्र की विज़िट हेतु मोबिलिटी सपोर्ट प्रदान किया जावे। इस गतिविधि की बुकिंग गतिविधि क्रमांक–A.1.5.14 में की जाय।

(फैज़ अहमद किदवई)
मिशन संचालक
o/c राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

पृ.क्र. / एन.एच.एम. / एम.एच. / 2014 / 822 भोपाल, दिनांक 02 / 12 / 2014

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त नोडल अधिकारी, जिला एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, मध्यप्रदेश।
2. समस्त नोडल अधिकारी, ए.आर.टी. केन्द्र, मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक
o/c राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

संचालनालय महिला सशक्तिकरण मध्यप्रदेश

महिला एवं बाल विकास विभाग
खण्ड दो चतुर्थ तल, पर्यावास भवन,अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश
ई- icpsbhopal@gmail.com www. mpwe.in

क्रमांक / मबावि / 14 / ICPS / 258 भोपाल, दिनांक / 1-02-2014

प्रति,

जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी /
जिला बाल संरक्षण अधिकारी
जिला –समस्त

विषय :– एचआईवी संक्रमित बच्चों को पोषण देखरेख / प्रवर्तकता योजना के तहत लाभान्वित करने के संबंध में ।

संदर्भ:– संचालनालय का पत्र क्रमांक 180 दिनांक 10.06.2013।

संदर्भित पत्र के माध्यम से आपको समेकित बाल संरक्षण योजनांतर्गत पालन पोषण देखरेख योजना की सम्पूर्ण प्रकिया की जानकारी दी जाकर नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था इसके अतिरिक्त समेकित बाल संरक्षण योजना मे एड्स द्वारा संक्रमित तथा प्रभावित बच्चों के लिये नियमानुसार पालन पोषण देखरेख अथवा प्रवर्तकता आदि सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिये विशेष प्रयास किये जाने का उल्लेख किये जाने के साथ ही किशोर न्याय(बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2003 के नियम 40 मे उक्त प्रकार के बच्चों को लाभान्वित किया जाना प्रावधानित किया गया है ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि अन्य पात्र हितग्राहियों के साथ आप जिले मे एचआईवी संक्रमित (पात्र बच्चों) को नियमानुसार लाभांवित करने की कार्यवाही कर प्रतिवेदन संचालनालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(प्रेमा सेठी)
संयुक्त संचालक
संचालनालय महिला सशक्तिकरण
भोपाल म.प्र.

क्रमांक / मबावि / 14 / ICPS / 259 भोपाल, दिनांक / 1-02-2014

प्रतिलिपि :– 1. संभागीय संयुक्त संचालक / संभागीय उपसंचालक समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। ।

2. अधीकक्षक / प्रबंधक, शासकीय / अशासकीय संस्थाएं जिला समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संयुक्त संचालक
संचालनालय महिला सशक्तिकरण
भोपाल म.प्र.

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)
59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, भोपाल
फोन 0755-2551486-87 फैक्स 2550094

क्र.6764/MGNREGS-MP/NR-1/15 भोपाल, दिनांक 30/6/2015

प्रति,

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला / जिला पंचायत ..... (समस्त) मध्यप्रदेश।

विषयः— एड्स नियंत्रण विभाग, स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के मध्य संपादित एम.ओ.यू के क्रियान्वयन बाबत्।

संदर्भः— परियोजना संचालक राज्य एड्स समिति का पत्र क्र.1741 दिनांक 22/06/2015

—oo—

कृपया संलग्न संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। एचआईव्ही/एड्स को मुख्यधारा में लाने हेतु एड्स नियंत्रण विभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के साथ दिनांक 10 जून 2015 को एम.ओ.यू संपादित किया गया है। उक्त एम.ओ.यू की धारा–2(2.6) में निम्नानुसार प्रावधान किया गया जो इस प्रकार है:—

"Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) aims at enhancial livelihood security by providing upto 100 days of guranteed wage employment in a financial year to every rural household. In view of the large rech of this programme, there is scope for dissmination of correct information and knowledge about prevention of HIV thorough peer approach at work sites.Besides the prevention effort, the employment provided under the programme is important."

कृपया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र. के अंतर्गत,उक्त एम.ओ.यू की धारा–2(2.6) मे दिये प्रावधानो का पालन किये जाने का कष्ट करें ताकि एड्स पीडित व्यक्ति के परिवारो को योजना का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सकें।

(डी.एस.रणदा)
अति.मुख्यकार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

MAHARASHTRA

Summary

- **Antyodaya Anna Yojana**
  Extended the benefits of AAY (Food Grains) under Targeted Public Distribution System to People Living with HIV in subsidized price.

- **Ration Card to Female Sex Workers**
  Extended the benefits of AAY (Food Grains) under Targeted Public Distribution System to People Living with HIV in subsidized price.

- **Financial Assistance (Sanjay Gandhi Niradhar Yojana)**
  Financial assistance Rs. 600/- per month to People Living with HIV.

- **Double Nutrition Support to Children Affected By AIDS**
  Double Nutrition support to Children infected and affected by AIDS.

- **Education for children of Female Sex Workers**
  Education support for children of Female Sex Workers

प्रसिद्धीपत्रक

मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत माहे, डिसेंबर-२०१२ साठी कौटुंबिक शिधापत्रिकेवर देय असलेल्या नियंत्रित शिधाजिन्नसांचे परिमाण व दर पुढीलप्रमाणे आहेत.

---

१. ए.पी.एल.- ए.पी.एल. शिधापत्रिकाधारकास वितरीत करावयाच्या धान्याचे परिमाण प्रति शिधापत्रिका प्रतिमाह एकूण १५ किलो, त्यापैकी ५ किलो तांदूळ रु.९.६० प्रती किलो व १० किलो गहू रु.७.२० प्रती किलो, असे आहे. मात्र ए.पी.एल. शिधापत्रिकाधारकास फक्त गहूच हवे असल्यास १५ किलोपर्यंत गहू घेता येईल.

२. बी.पी.एल.- (अ) बी.पी.एल. योजनेच्या प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकास वितरीत करावयाच्या धान्याचे परिमाण प्रतिमाह एकूण ३५ किलो असून त्यापैकी २५ किलो तांदूळ रु. ६.०० प्रतिकिलो व १० किलो गहू रु. ५.०० प्रतिकिलो, असे आहे. सदर शिधापत्रिकाधारकांना बी.पी.एल. दराचे ३५ किलो धान्य महिन्यामध्ये एकाचवेळी उचलणे शक्य नसल्यास त्यांना ते धान्य दोन टप्प्यांमध्ये घेता येईल.

(ब) बी.पी.एल. योजनेच्या लाभार्थ्यांना, उपरोक्त परिमाणाव्यतिरिक्त प्रतिमाह प्रति शिधापत्रिका ५ किलो धान्य त्यापैकी १ किलो तांदूळ व ४ किलो गहू या परिमाणानुसार तांदूळ रु. ६.०० प्रतिकिलो व गहू रु. ५.०० प्रतिकिलो, दराने तदर्थ/अतिरिक्त नियतनाचे वितरण करण्यात येईल.

उपरोक्त (अ) व (ब) नुसार बीपीएल योजनेच्या लाभार्थ्यांना माहे डिसेंबर, २०१२ मध्ये प्रति शिधापत्रिका, नियमित व तदर्थ/अतिरिक्त धान्य असे एकूण (३५+५)= ४० किलो धान्य वितरीत करण्यात येईल.

३. अंत्योदय - (अ) अंत्योदय अन्न योजनेचे लाभार्थी असे शिक्के मारलेल्या प्रत्येक शिधापत्रिकेवर वितरीत करावयाच्या धान्याचे परिमाण प्रतिमाह एकूण ३५ किलो असून त्यापैकी २५ किलो तांदुळ रु. ३.०० प्रतिकिलो व १० किलो गहू रु. २.०० प्रतिकिलो, असे आहे. अंत्योदय अन्न योजनेचे ३५ किलो धान्य दोन टप्प्यांमध्ये घेण्याची शिधापत्रिकाधारकांना मुभा असून जे शिधापत्रिकाधारक सदर धान्य एका टप्प्यात घेऊ इच्छित असतील, त्यांना ते एकाच टप्प्यात सुद्धा घेता येईल.

(ब) अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थ्यांना, उपरोक्त परिमाणाव्यतिरिक्त प्रतिमाह प्रति शिधापत्रिका ५ किलो धान्य त्यापैकी १ किलो तांदूळ व ४ किलो गहू या परिमाणानुसार तांदूळ रु. ६.०० प्रतिकिलो व गहू रु. ५.०० प्रतिकिलो, या बी.पी.एल. दराने तदर्थ/अतिरिक्त नियतनाचे वितरण करण्यात येईल.

उपरोक्त (अ) व (ब) नुसार अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थ्यांना माहे डिसेंबर, २०१२ मध्ये प्रति शिधापत्रिका, नियमित धान्य अंत्योदय दराने व तदर्थ/अतिरिक्त धान्य बीपीएल दराने असे एकूण (३५+५)= ४० किलो धान्य वितरीत करण्यात येईल.

४. अन्नपूर्णा - केंद्रिय अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत ६५ वर्षावरील निराधार व्यक्तिंना वितरीत करावयाच्या धान्याचे परिमाण प्रतिमाह १० किलो (त्यापैकी तांदूळ ५ किलो व गहू ५ किलो) असे आहे. सदर १० किलो धान्य हे संपूर्णत: मोफत आहे.

५. साखर - दारिद्र्य रेषेखालील पिवळ्या शिधापत्रिकाधारकांसाठी माहे डिसेंबर -२०१२ करिता साखरेचे मासिक परिमाण दरमाणशी ५०० ग्रॅम साखर रु. १३.५० प्रतिकिलो, असे आहे. ज्या पिवळ्या शिधापत्रिकाधारकांना माहे नोव्हेंबर -२०१२ चा साखरेचा कोटा मिळाला नसेल, त्यांना तो कोटा माहे डिसेंबर -२०१२ मध्ये घेता येईल.

C:\Documents and Settings\NanduC\Desktop\Website Infromation\Prasiddhipatrak\Prasiddhipatrak Dec-12.doc

६. केरोसीन - शासन पत्र दिनांक ५ ऑगस्ट, २००५ अन्वये आश्वासित केरोसीन योजना राबविण्यात आली असून, त्यानुसार माहे डिसेंबर, २०१२ करिता मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रात परिमंडळनिहाय आरंभीची शिल्लक व माहे डिसेंबर, २०१२ साठी शासनाकडून प्राप्त नियतन (३८.४६%) असा एकूण उपलब्ध होणारा (३९.९७%) केरोसीन कोट्यानुसार शिधापत्रिकांवरील देय केरोसीन पुढीलप्रमाणे आहे.

केरोसीनचे परिमाण

माहे नोव्हेंबर, २०१२ अखेर शिल्लक (कि.लि.)	माहे डिसेंबर, २०१२ चे नियतन (कि.लि.)	आश्वासितप्रमाणे शिधापत्रिकाधारकांना देय परिमाण (लिटर)							
		१ गॅस	१ व्यक्ती	२ व्यक्ती	३ व्यक्ती	४ व्यक्ती	५ व्यक्ती	६ व्यक्ती	७ व्यक्ती व वरील
५५९.७५२	१४२३२	२	२	५	६	७	८	९	१०

केरोसिनचे दर

मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील मुंबई विभागासाठी शासन परिपत्रक क्रमांक रॉकेल-१५१२/प्र.क्र.२०८, ना.पु.२७, दि.२६ जुलै, २०१२ नुसार केरोसिनचा दर प्रती लिटर रु.१४.४४ असा आहे.

ठाणे विभागासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी यांनी ठरवून दिलेल्या दरानुसार उप नियंत्रक शिधावाटप, 'फ' परिमंडळ यांचे पत्र क्रमांक फप/केरो/२०१२/काबि.२१२/जा.३५२३, दिनांक ३०/०७/२०१२ नुसार केरोसीनचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत.

अ.क्र.	शिधावाटप कार्यालय	क्षेत्र	दर
१.	ठाणे विभाग (३६/फ, ४१/फ, ४८/फ)	ठाणे म.न.पा. क्षेत्र	१४.६३
२.	४१/फ वाशी	ठाणे म.न.पा. क्षेत्र वगळून	१४.५०
३.	४१/फ भाईंदर	मिरा भाईंदर म.न.पा. क्षेत्र	१४.६७
४.	३८/फ कल्याण	कल्याण डोंबिवली म.न.पा. क्षेत्र	१४.५९
५.	३९/फ डोंबिवली	कल्याण डोंबिवली म.न.पा. क्षेत्र वगळून	१४.५९
६.	४०/फ उल्हासनगर	उल्हासनगर म.न.पा. क्षेत्र	१४.६३
७.	४०/फ (उप) उल्हासनगर		
८.	४६/फ (अंबरनाथ), ४६/फ (बदलापूर)	उल्हासनगर (बिगरजकात क्षेत्र)	१४.६३
९	३७/फ भिवंडी	म.न.पा. क्षेत्र	१४.६९
१०.		म.न.पा. क्षेत्र वगळून	१४.५५

शासनाकडून प्राप्त होणारे मासिक नियतन, दर अथवा परिमाणात बदल झाल्यास त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.

सही/-
नियंत्रक शिधावाटप व
संचालक नागरी पुरवठा,
मुंबई.

C:\Documents and Settings\NanduC\Desktop\Website Infromation\Prasiddhipatrak\Prasiddhipatrak Dec-12.doc

क्र.निशि/मागणी/१०२०१२/दोन/जा.९८२
नियंत्रक शिधावाटप व संचालक
नागरी पुरवठा यांचे कार्यालय,
एक्सप्रेस इमारत, २ रा मजला,
चर्चगेट, मुंबई - ४०० ०२०.

दिनांक : ११/१२/२०१२

प्रति,

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांस वरील वृत्तास व्यापक प्रसिध्दी देण्याच्या विनंतीसह सस्नेह अग्रेषित.

सही/-
नियंत्रक शिधावाटप व
संचालक नागरी पुरवठा,
मुंबई.

प्रत माहितीस्तव अग्रेषित :-

१. मा. राज्यमंत्री, अनापु व ग्रासंवि आणि साबांवि, मंत्रालय, मुंबई.
२. मा.खासदार, सर्व मुंबई/ठाणे शिधावाटप क्षेत्र, (संबंधीत परिमंडळामार्फत)
३. मा.आमदार, सर्व मुंबई /ठाणे शिधावाटप क्षेत्र, (संबंधीत परिमंडळामार्फत)
४. मा.महापौर, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे,कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका (संबंधीत परिमंडळामार्फत)
५. मा.आयुक्त, महानगरपालिका, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका (संबंधीत परिमंडळामार्फत)
६. मा.नगराध्यक्ष, अंबरनाथ, बदलापूर. (संबंधीत परिमंडळामार्फत)
७. उपसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
८. वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, ४२ सर वि.ठा.मार्ग, मुंबई
९. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन क्र.२२ व २८ अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई
१०.पर्यवेक्षक अधिकारी, श्रम मंत्रालय,७१ बी श्रम साफल्य, एन.जी.आचार्य मार्ग, चेंबूर, मुंबई ७१.
११. रेशनिंग कृती समिती, आर.एच.४, सी-४, लेन-८, सेक्टर-९, सी.बी.डी., बेलापूर, नवी मुंबई-४००६१४
१२. श्री. रेडकर संघटक, घरकाम मोलकरीण संघटना, भुपेश गुप्ता भवन, ८५-सयानी रोड, प्रभादेवी, मुंबई.
१३. घरकाम मोलकरीण संघटना, मुंबई जिल्हा अंधेरी, घन:श्याम पाटील चाळ,एस.व्ही.रोड,अंधेरी (प), मुंबई-५८
१४. विशेष कार्यकारी अधिकारी, कामगार आयुक्तांचे कार्यालय, कामगार भवन, सी-२०, ई ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुं-५१.
१५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सह.पणन महासंघ मर्या.,कनमूर हाऊस, नरसी नाथा स्ट्रीट, मुंबई.
१६. संदीप सुमन,रेशनिंग व जिविका हक्क संघटना, ई-३१, महात्मा गांधी स्मृती वसाहत, जेरबाई वाडीया रोड, परेल, भोईवाडा,मुंबई -१२.

प्रत आवश्यक त्या कार्यवाहीस्तव अग्रेषित :-

१. उपनियंत्रक शिधावाटप, सर्व परिमंडळ कार्यालये.
२. उप संचालक (गो), संचालनालय नागरी पुरवठा (गो/वा), पुरवठा भवन, परेल, मुंबई.
३. शिधावाटप अधिकारी, सर्व शिधावाटप कार्यालये.
४. सर्व संघटित संस्था, (परिमंडळ कार्यालयामार्फत.)
५. कार्यासन अधिकारी, का.क.३ (साखर), ५ (दक्षता), ६ (केरोसिन), ११ (प्रशासन) व नियंत्रण कक्ष, प्रधान कार्यालय.

C:\Documents and Settings\NanduC\Desktop\Website Infromation\Prasiddhipatrak\Prasiddhipatrak Dec-12.doc

वेश्या, बालवेश्या व वेश्यांच्या मुलांच्या
पुनर्वसनासाठी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत-
शिधापत्रिका देणे...

महाराष्ट्र शासन,
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग,
शासन निर्णय, क्र. सावित्र्य-११९९/३६७०/प्र.क्र. ८८५८/नापु-२८,
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२,
दिनांक : 29 सप्टेंबर, १९९९.

शासन निर्णय :- केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार वेश्या व्यवसायास प्रतिबंध करण्यासाठी, बालवेश्या व वेश्यांच्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी एक सल्लागार समिती स्थापन केली आहे. या समितीने अशा लैंगिक शोषित स्त्री कुटुंबप्रमुखास लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत एक विशेष पात्र प्रवर्ग म्हणून शिधापत्रिका देण्याची सूचना केली आहे. शासनाने सदर सूचना मान्य केली आहे. त्यानुसार वेश्या, बालवेश्या व वेश्यांच्या मुलांचे पुनर्वसन होण्याकरीता अशा लैंगिक शोषित स्त्री कुटुंब प्रमुखास, त्यांनी शिधापत्रिकेसाठी अर्ज केल्यास प्रचलित पध्दतीनुसार आवश्यक असलेले पुरावे सादर करण्यामध्ये त्यांना येणाऱ्या अडचणींचा सहानुभूतिपूर्वक विचार करून, अजाण, नमूद केलेल्या ठिकाणी त्यांचे प्रत्यक्ष वास्तव्य आहे किंवा कसे व त्या ठिकाणी त्या स्वयंपाक करतात किंवा नाही याची खात्री करावी आणि प्रचलित पध्दतीचा अवलंब करून त्यांना एक विशेष पात्र प्रवर्ग म्हणून लक्ष्य निर्धारीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत शिधापत्रिका देण्यात यावीत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

[पां. जी. माधव]
कार्यासन अधिकारी,
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग.

प्रति,
१] सर्व विभागीय आयुक्त.
२] सर्व विभागीय उप आयुक्त (पुरवठा)
३] सर्व अपर जिल्हाधिकारी,
४] नियंत्रक शिधावाटप, मुंबई.
५] सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी.
६] सर्व मंत्रालयीन विभाग.
७] महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. [५ प्रती]
८] वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई.
९] संचालक, नागरी पुरवठा [नो/[illegible]]
१०] [illegible] आयुक्त, [illegible] कार्यालय, [illegible]
११] [illegible], अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.
१२] [illegible] [निवड नस्ती]

181

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना
सन २०१०-११ या आर्थिक वर्षातील तरतूदींचे
उणे पध्दतीने वाटप करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,
शासन निर्णय क्रमांक बीयुडी-२०१०/प्र.क्र.२५/विसयो-१
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२.
दिनांक : २५ ऑक्टोबर,२०१०

वाचा :- १) शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र.मकोनि-१०१०/प्र.क्र.३२/कोषा प्र-५, दिनांक १५ एप्रिल, २०१०.
२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. बीजीटी-२०१०/प्र.क्र.१८७/अर्थसंकल्प, दिनांक २० एप्रिल,२०१०
३) शासन निर्णय क्रमांक विसयो-२००८/प्र.क्र.७८/विसयो-१, दिनांक ३० सप्टेंबर,२००८
४) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र.बीयुडी-२०१०/प्र.क्र.२५/विसयो-१, दि.२५-६-२०१०.

प्रस्तावना : सामाजिक अर्थसहाय्य कार्यक्रमांतर्गतच्या राज्य शासन पुरस्कृत संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेची देयके उणे पध्दतीने काढण्याबाबत वित्त विभागाने शासन परिपत्रक क्र.मकोनि-१०१०/प्र.क्र.३२/कोषा प्र-५, दिनांक १५ एप्रिल, २०१० अन्वये आदेश निर्गमित केले आहेत. व हे परिपत्रक संगणक सांकेतांक २०१००४१५१५०४४५००१ वर उपलब्ध आहे. याला अनुसरुन सामाजिक न्याय विभागाने उपरोक्त संदर्भ क्र.२ चे शासन परिपत्रक बीजीटी-२०१०/प्र.क्र.१८७/अर्थसंकल्प, दिनांक २० एप्रिल,२०१० निर्गमित केले व त्याची प्रत सर्व कार्यालयांना पाठविलेली आहे.

शासन निर्णय :- वरील बाब विचारात घेऊन उणे पध्दतीने देयके काढण्यासाठी प्रत्येक जिल्हयाने संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेची सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात सूचित केलेल्या रकमेच्या मर्यादेत देयके काढावीत. याबाबत सदर तरतुदीच्या मर्यादेत हा खर्च तात्काळ करण्यात यावा.

राज्य शासन पुरस्कृत सामाजिक अर्थसहाय्य कार्यक्रमांतर्गतच्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या रु.२६३४३.८२ लाख खर्चासाठी "महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक २०१०" विधानमंडळात मंजूर केले असून त्या अन्वये मंजूर झालेल्या तरतूदीपैकी माहे एप्रिल व मे,२०१० या दोन महिन्यांसाठी रु.४३९०.६१ लाख इतकी तरतूद दि.२९ एप्रिल,२०१० च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आली होती. तसेच माहे जून,२०१० व मार्च,२०११ या कालावधीकरिता सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे उर्वरित रु.२१९५३.२१ लाख इतकी तरतूद वित्त विभागाच्या दि.१५ एप्रिल,२०१० या संदर्भ क्र.१ व २ अन्वये उणे पध्दतीने काढण्यास दि.२५ जून,२०१० च्या शासन निर्णयाद्वारे निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिलेली आहे. आता महाराष्ट्र विधानमंडळाने मंजूर केलेल्या "महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक २०१०" अन्वये संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी पुरक मागणीद्वारे उपलब्ध करुन घेतलेल्या अतिरिक्त र.१००००.०० लक्ष इतकी रक्कम सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन मान्यता देत आहे.

182

२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी यासोबत जोडलेल्या विवरणपत्राद्वारे वितरीत केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना आवश्यकतेनुसार करावे. सदरचे अनुदान वितरण जिल्हाधिकाऱ्यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार करण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांना अनुज्ञेय असलेले अनुदान बँक खाते / पोस्ट बचत खाते (पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग खाते) यामार्फतच वितरीत करण्यात यावे.

३. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विसयो-२००८/प्र.क्र.७८/विसयो-१, दिनांक ३० सप्टेंबर,२००८ मध्ये लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य वितरणासंबंधातील जी पध्दती निर्धारित केली आहे त्याच पध्दतीने या योजनेमधील लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य वितरीत करण्यात यावे. सदरहू वितरीत अनुदान "मागणी क्रमांक एन-३ मुख्य लेखाशीर्ष २२३५ ,सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ ,समाजकल्याण ,१०४, वृध्द विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण (०८)(०९) संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (२२३५ अे २९४) ५०-इतर खर्च" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा.

४. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी.

५. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाच्या विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित पाठवावे व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील.

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून, त्याचा संगणक क्रमांक - २०१०१०२५२१४५४३००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

(ग. कि. वाघ)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति
सर्व विभागीय आयुक्त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद
सर्व जिल्हाधिकारी.
संचालक ,लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती)
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर.
वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई
अवर सचिव (अर्थसंकल्प) सा.न्या.सां.का.वि.स. विभाग,मंत्रालय, मुंबई.
निवड नस्ती, विसयो १

183

Release Order for Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana

Amount Budgeted 36343.82

Amount already released 26343.82

Balance 10000

(Rs.In Lakhs)

Serial Number		District	Number of Beneficiaries	Amount Required		Amount Released
1		Mumbai	1681	100.86		36.32
2		MSD	3343	200.58		72.24
3		Thane	6269	376.14		135.46
4		Raigad	5584	335.04		120.66
5		Ratnagiri	4388	263.28		94.82
6		Sindudurg	4030	241.8		87.08
				0		0
7		Pune	8365	501.9		180.75
8		Satara	5191	311.46		112.17
9		Sangli	11635	698.1		251.41
10		Solapur	26176	1570.56		565.62
11		Kolhapur	10732	643.92		231.9
			0	0		0
12		Nashik	9000	540		194.47
13		Dhule	16740	1004.4		361.72
14		Nandurbar	4153	249.18		89.74
15		Jalgaon	11937	716.22		257.94
16		Ahmednagar	13290	797.4		287.17
			0	0		0
17		Aurangabad	55120	3307.2		1191.05
18		Jalna	20013	1200.78		432.45
19		Beed	18792	1127.52		406.06
20		Parbhani	16318	979.08		352.6
21		Latur	17990	1079.4		388.73
22		Nanded	19599	1175.94		423.5
23		Osmanabad	18600	1116		401.91
24		Hingoli	10150	609		219.32
			0	0		0
25		Amaravati	14510	870.6		313.54
26		Akola	1200	72		25.93
27		Washim	14380	862.8		310.73
28		Buldhana	19500	1170		421.36
29		Yavatmal	16500	990		356.54
			0	0		0
30		Nagpur	29000	1740		626.64
31		Wardha	8500	510		183.67
32		Bhandara	11000	660		237.69
33		Gondia	9900	594		213.92
34		Chandrapur	12700	762		274.42
35		Gadchiroli	6500	390		140.45
		Total :	462786	27767.16		10000

HIV/AIDS बाधित बालकांना तीव्र कमी वजनाच्या बालकांसाठी अनुज्ञेय असलेला आहार देणे बाबत..

महाराष्ट्र शासन
महिला व बाल विकास विभाग
शासन निर्णय ,क्रमांक :एबावि २०११ / प्र.क्र. ५६ /का-५
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.
दिनांक :- २६ एप्रिल , २०११

वाचा :- १) महिला व बाल विकास विभाग , शासन निर्णय क्र.एबावि-२००८/प्र.क्र.५९/का-५ दिनांक २४.८.२००९ .
२) ममता हेल्थ इंस्टिट्यूट फॉर मदर ॲण्ड चाईल्ड ,नागपूर यांचे दिनांक ३.१२.२०१० चे पत्र
३) आयुक्त, महिला व बाल विकास विभाग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र मयावि/एबाविसेयो/का-२/१११३/१०.११, दिनांक १६.२.२०११

शासन निर्णय :- संदर्भांकित अनुक्रमांक (१) येथील दिनांक २४.८.२००९ च्या शासन निर्णयान्वये एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेतर्गत ६ महिने ते ६ वर्ष वयोगटातील तीव्र कमी वजनाच्या बालकांना ८० उष्मांक व २० ते २५ ग्रॅम प्रथिने असलेला आहार तसेच नवसंजीवन क्षेत्रातील तीव्र कमी वजनाच्या बालकांना ९५ उष्मांक आणि २३ ते २८ ग्रॅम प्रथिने असलेला आहार देण्यात येतो. त्याप्रमाणेच ६ महिने ते ६ वर्ष वयोगटाती HIV/AIDS बाधित बालकांना तीव्र कमी वजनाच्या बालकांसाठी अनुज्ञेय असलेला पुरक पोषण आहार देण्या शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

२. सदरची बालके ज्या अंगणवाडीच्या परिक्षेत्रात रहात असतील त्या परिक्षेत्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच वैद्यकीय अधिका-यांनी आवश्यक वैद्यकीय प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच अंगणवाडी सेविकेव्दारे सदर बाधित बालकांना ती कमी वजनाच्या बालकांना अनुज्ञेय असणारा आहार देण्यात यावा.

३. सदरची बालके अंगणवाडीमध्ये नियमितपणे उपस्थित रहात नसली तरी सुध्दा संबंधित बालकांच पालकांमार्फत त्यांना अंगणवाडी सेविकेव्दारे घरपोच आहार पुरविण्यात यावा.

. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने.

(ज.कि.मगरे)
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,
आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय , महाराष्ट्र राज्य, पुणे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा, (महिला व बाल विकास आयुक्तालय पुणे यांचे मार्फत)
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण / ग्राम पंचायत), (महिला व बाल विकास आयुक्तालय , पुणे यांचे मार्फत)

G.R.2011

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९
देहविक्री करणाऱ्या महिला व तृतीयपंथी यांच्या मुलांना शाळेमधील प्रवेश देण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
शासन निर्णय क्रमांकः पिआरई २०१३/प्र.क्र.१२१/प्राशि-१
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२
तारीख: २७ मे, २०१३

शासन परिपत्रक -

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ याची अंमलबजावणी दिनांक १ एप्रिल, २०१० पासून राज्यात सर्वच समाज घटकांच्या बालकांसाठी सुरू आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने दिनांक ११ ऑक्टोबर, २०११ रोजी नियम अधिसूचित केले आहेत. या अधिनियमातील तरतूदीनुसार ६ ते १४ वयोगटातील बालकाला इयत्ता १ ते ५ या वर्गाचे मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद आहे.

२. देहविक्री करणाऱ्या महिला आणि तृतीयपंथी यांच्या सामाजिक समावेशनाकरिता आराखडा तयार करण्यासाठी दिनांक ९ एप्रिल, २०१३ व २९ एप्रिल, २०१३ रोजी मा.मुख्य सचिवांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित केली होती. त्या बैठकीमध्ये देहविक्री करणाऱ्या महिलांची बालके अथवा तृतीयपंथी यांच्या कुटुंबातील बालके यांना शाळा प्रवेश देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ चे कलम ८ व ९ नुसार, ६ ते १४ वयोगटातील बालकांना शाळेत प्रवेश देवून त्यांचे इयत्ता १ ते ८ शिक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासन व स्थानिक प्राधिकरणाची आहे.

या बाबी विचारात घेवून देहविक्री करणाऱ्या महिलांची बालके अथवा तृतीयपंथी यांच्या कुटुंबातील बालके यांना शाळा प्रवेश देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे आढळल्यास प्रचलित तरतूदीनुसार संबंधित बालकांना शाळेत वयानुरूप प्रवेश मिळवून देण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करावी. या संवर्गातील बालकांच्या वडिलांचे नाव व निवासाचा पुरावा याबाबतची माहिती उपलब्ध होत नसेल तर

सदर माहिती देण्याबाबत सक्ती न करण्याच्या सूचना सर्व शाळांना देण्यात याव्यात. या दुर्लक्षित समाज घटकांच्या प्रश्नावर कार्यरत असणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांकडून शाळा प्रवेशातील अडचणींबाबत संपर्क झाल्यास त्यांना देखील आवश्यक सर्व सहकार्य करावे अशा सूचना सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)/(माध्यमिक), शिक्षण निरिक्षक व प्रशासन अधिकारी यांना देण्यात येत आहेत. महिला व बालविकास विभागाने या समाज घटकांच्या प्रश्नांवर कार्यरत असणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सदर परिपत्रक निदर्शनास आणावे.

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०५२७१६१६५८१३२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

Nana Uttamrao Raurale

Digitally signed by Nana Uttamrao Raurale
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=School Education & Sports Dept, postalCode=400032, st=Maharashtra, cn=Nana Uttamrao Raurale
Date: 2013.05.27 16:26:07 +05'30'

(ना.उ.रौराळे)
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,
२. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण),
३. मा. राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण),
४. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक,
५. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,
६. सर्व प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई,
७. सर्व विभागीय आयुक्त,
८. संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई
९. सचिव, राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, शासकीय परिवहन सेवा केंद्राजवळ, वरळी पोलिस कॅम्प, वरळी, मुंबई - २५
१०. सर्व जिल्हाधिकारी,
११. सर्व आयुक्त, महानगरपालिका,
१२. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,
१३. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई,
१४. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे,

१५. शिक्षण संचालक(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
१६. शिक्षण संचालक(प्रौढ शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
१७. संचालक, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे,
१८. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे,
१९. संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ(बालभारती), पुणे,
२०. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ,
२१. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक,
२२. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक/प्रौढ), जिल्हा परिषद,
२३. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका/ नगर परिषद,
२४. सर्व प्रशासन अधिकारी, नगर परिषद/ कटक मंडळे,
२५. शिक्षण निरीक्षक (पश्चिम/ दक्षिण/ उत्तर), बृहन्मुंबई
२६. निवड नस्ती (प्राशि-१ कार्यासन)